(SHRI G. VENKATSWAMY): (a) The Minimum Wages Act which provides for payment of wages at rates not below those fixed under the Minimum Wages Act is being strictly enforced by the Central Government.

(b) Central Industrial Relations Machinery (CIRM) has been set-up for prevention and settlement of industrial disputes, labour inspections, enforcement of various labour laws including Minimum Wages Act in industries/ employments for which appropriate Government is the Central Government. It also carries out certain functions relating to verification of membership of trade unions in the Country.

(c) CIRM was set up in April, 1945. Average amount being spent annually during 1992-93 to 1994-95 is Rs. 6.3 crores, (total of Plan and Non-plan expenditure). A statement is enclosed *(see* below).

(d) Information regarding number of inspections, irregularities detected, irregularities regarding less payment, claim cases filed and decided, prosecution cases filed and decided for the period from 1990 to 1994 is given in a tabulated from attached herewith (Annex.) *[See* Appendix 175, Annexure No. 38].

As regards, the States with maximum and minimum number of irregularities, it is stated that the State of Orissa; leads in the number of irregularities detected while the minimum number of irregularities were detected in the state of Kerala.

Statement

Details showing expenditure incurred by CIRM during the' period from 1992-93 to 1995-96

(Rupees in thousands)

Year	Non-plan	Plan	Total
1. 1992-93	4,95,03	66,95	5,61,98
2. 1993-94	5,53,92	83,93	6,37,85
3. 1994-95	5,83,29	93,51	6,76,80
4. 1995-96 (upto Sept., 95)	3,70,86	50,39	4,21,25

Average Expenditure for the first three year from 1992-93 to 1994-95 = Rs. 625,54 thousand or say Rs. 6.3 crore.

Number of land oustccs from Orissa Coal Fields

1368. SHRI RAHASBIHARI BARIK:
SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the number of land oustees on different coal fields in Talcher, Anugul and other parts of Orissa;

{b) whether Government have taken steps to provide jobs and compensation to the affected families and their kith and kin;

(c) if not, the number of cases which have not been settled so far; and

(d) the details therefor with action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Number of land losers identified in various on going projects/coalfields in Orissa are as under:—

1. Talcher Coalfields — 4840

2. Talcher Valley Coalfields—2558 (excluding Gopalpur).

(b) Affected families are paid compensation for the land acquired as per the provisions of law. Jobs andfor rehabilitation benefits are provided to the land oustees and their kith and kin as per the guidelines issued by the Government of Orissa.

(c) and (d) As informed by company, there is no such case pending with the management of the company.

पश्चिमी बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड को घटिया कोयले की आपूर्ति किया जाना

1369. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तापीय विद्युत संयंत्रों को अपर्याप्त एंव घटिया कोयलों की आपूर्ति किये जाने के कारण विद्युत उत्पादन निरन्तर प्रभावित होता रहा है,

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पश्चिमी बंगाल बिजली विकास निगम लि. के विभिन्न संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति होती जा रही है,

(ग) उपर्युक्त संयंत्रों को कोयले की 45 प्रतिशत आपूर्ति करने की जिम्मेदारी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की है और आपूर्ति किये गये कोयले में 55 प्रतिशत राख होती है,

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों को समय पर अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए है, और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तापीय विद्युत संयत्रों को कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में तथा सहमति हुई गुणवत्ता में जिसके लिए उनके बायलर को अभिकल्पित किया गया है, कि आपूर्ति की गई है । आमतौर पर गुणवत्ता संबधी शिकायतें प्राप्त होती है, जो विद्युत गृहों को आपूर्ति किये जा रहे, कोयले में बाह्य सामग्री की विद्यमानता तथा कोयले की बड़े आकार में आपूर्ति होने के संबंध में होती है, इन शिकायतों पर प्रत्येक मामले में गुणवत्ता आधार पर जाचं की जाती है तथा उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायि किये जाते हैं ।

(ख) और (ग) कोलाघाट तापीय विद्युत संयंत्र (के.टी.पी.पी.) जो कि पश्चिमी बंगाल विद्युत विकास निगम लि. (डब्ल्यू. बी.पी.डी.सी.एल.) का एक मात्र संयंत्र है, महानदी कोलफील्ड्स लि. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. से कोयला की आपूर्ति प्राप्त करता है । कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोलाघाट तापीय विद्युत संयंत्र से प्राप्त विश्लेश्षण के परिणामों के अनुसार कोयले में राख के तत्व 35% सीमा तक की रेंज कें होने की पुष्टि करते हैं ।सितम्बर-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान कोलाघाट तापीय विद्युत संयंत्र में स्थापित क्षमता का 105% विद्युत उत्पादन का रिकार्ड हासिल किये जाने की सूचना मिली है ।

(घ) और (ड.) विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण किए जाने की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कों.इं.लि. तथा रेलवे द्वारा उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

कृषि उत्पादों के निर्यात से आय का सृजन

1370. **श्री अजीत जोगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय कृषि उत्पादों के निर्यात से राज्य-वार कितनी आय होती है और आगामी तीन वर्षों में कितनी आय होने का अनुमान है ,

(ख) कृषि संबंधी निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से मूलभूत ढांचा तैयार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए पूंजी निवेश संबंधी दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) कृषि-उत्पादों के निर्यात हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिंदम्बरम): (क) राज्य-वार निर्यात के आंकडे नहीं रखे जाते हैं । तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि-जन्य और सम्बद्ध उत्पादों (काफी, चाय, कपास और समुद्री उत्पादों को छोड़कर) के कुल निर्यात की कीमत नीचे दी गयी हैः-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रूपए में)
1992-93	5686.81
1993-94	7532.99
1994-95	7049.05
1995-96 (अगस्त, 1995 तक)	3265.77

(स्त्रोतः डी.सी.जी.आई. एंड एस. कलकत्ता)